नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) तेल वर्ष (नवम्बर–अक्तूबर) 1993–94 के दौरान देश में खाद्य तेलों का अनुमानित उत्पादन, 67.20 लाख मीटरी टन की अनुमानित मांग के मुकाबले 61.70 लाख मीटरी टन था । वित्तीय वर्ष 1993–94 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा 51,04 करोड़ रुपए मूल्य के 41,965 मी. टन खाद्य तेल का आयात किया गया था । वर्ष के दौरान यू.एस.एड के तहत राज्य व्यापार निगम को उपहार स्वरूप अपरिष्कृत सोयाबीन के तेल की भी 37,000 मी. टन मात्रा प्राप्त हुई थी सरकार की निर्यात और आयात नीति के तहत 5 कि. ग्रा. तक के उपभोक्ता पैकों में चुने हुए खाद्य तेलों के निर्यात की अनुमति है। निर्यात की मात्रा न्यूनतम है और निर्यात की गई वास्तविक मात्रा के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) राज्य व्यापार निगम के पास 1–4–1993 और 31–12–1993 को खाद्य तेल का स्टाक निम्नवत था :—

(मात्रा मी.टन में)

तारीख	आर.बी.डी. पामोलीन	अपरिष्कृत सोयाबीन तेल
1–4–93	5820	21917
31–12–93	32163	—

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा खाद्य तेल की खरीद लागत, बीमा, भाड़ा आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से की जाती हैं। इन प्रभारों में से प्रत्येक की कीमत अलग से उपलब्ध नहीं है । वस्तुओं जिनमें खाद्य तेल शामिल हैं, के निर्यात हेतु सेवा प्रभारों में अलग-अलग पत्तनों और भिन्न-भिन्न वस्तुओं के मामले में अन्तर होता है । प्रत्येक किस्म के लिए खाद्य तेलों के देशीय मूल्य भिन्न-भिन्न हैं ।

HRA case of BIS

7571. SHRI MISA R. GANESAN: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that house rent allowance case of the employees of Bureau of Indian Standards is pending with Finance Ministry and Finance Ministry is awaiting for Vth Central Pay Commission recommendations; and

(b) if BIS does not come in purview of Vth Central Pay Commission then the reasons for the case being pending till Vth CPC recommendations?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b) As BIS employees accepted a package of pay and allowances including HRA on the basis of Fourth Central Pay Commission recommendations. Ministry of Finance has advised to wait for Vth Central Pay Commission report before any change in the HRA is considered.

Laboratories of BIS

7572. SHRI MISA R. GANESAN: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that laboratories of Bureau of Indian Standards are well equipped and each machine costs lacs of Rupees;

(b) whether it is also a fact that some machines are not utilised even for a single day; and

(c) steps taken to commercialise BIS labs to earn more revenue?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) Yes, Sir. Some of the equipments are highly specialised and costly.